प्रकाशनार्थ

पटना, 8 मार्च। इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर (आइजीसी) और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) ने बिहार सरकार के महिला विकास निगम के साथ मिलकर महिला दिवस मनाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसका शीर्षक था ''महिलाओं का सशक्तीकरण - मुद्दे, साक्ष्य और नीतिगत प्रतिक्रिया''। सम्मेलन का उद्घाटन बिहार सरकार के विकास आयुक्त अमीर सुभानी (भाप्रसे) और महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बम्हरा (भाप्रसे) द्वारा किया गया।

सम्मेलन में आद्री के सदस्य सचिव प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने कहा कि लैंगिक अंतराल में कमी लाने के मामले में बिहार का मिला-जुला प्रदर्शन रहा है। जहां प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक अंतराल घटा है, मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, महिलाओं और पुरुषों के काम एक ही प्रकार के हैं, और बाल लिंग अनुपात में सुधार हुआ है, वहीं बिहार में पुरुषों की तुलना में दूनी वयस्क महिलाएं असाक्षर हैं, और महिला श्रमशक्ति सहभागिता देश में सबसे कम है (विश्व बैंक समूह, 2016)। 13 संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स और प्राथमिकता आधारित 62 सूचकों के आधार पर 0 से 100 के पैमाने पर बिहार का संयुक्त स्कोर 48 है। इसके कारण बिहार को सिर्फ दो राज्यों - असम और उत्तर प्रदेश - के साथ 'आकांक्षी राज्य' का दर्जा दिया गया है।

पश्चिम ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र की प्रोफेसर अनु राममोहन ने कहा कि भारत में महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर घट रही है जो अभी पुरुषों के लिए 82 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत से भी नीचे है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद की दुनिया में महिलाओं को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें अधिक हिंसा, इंटरनेट सेवाओं की कम उपलब्धता और नए काम पाने की अक्षमता शामिल है। उनके विशेष व्याख्यान की अध्यक्षता बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग की प्रधान सचिव डॉ. एन. विजय लक्ष्मी ने की। उन्होंने फ्रंट लाइन के कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए बिहार सरकार की पहल ग्राम वार्ता और महिला विकास निगम के हस्तक्षेप को साझा किया ।

उद्घाटन सत्र में बिहार सरकार के विकास आयुक्त अमीर सुभानी ने सबसे हाल के राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में दिए गए सामाजिक-आर्थिक सूचकों के लिहाज से बिहार के विकास की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार में कुल प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3 रह गया है। लेकिन जन्मकालीन लिंग अनुपात में गिरावट आई है। इसका कारण उन्होंने अवैध लैंगिक-पहचान केंद्रों को बताया जिनके चलते महिला भ्रूणहत्या हो रही है। सरकार लोगों की जागरूकता बढ़ाने पर काम कर रही है ताकि वे महिला भ्रूणहत्या का विरोध करें। वहीं, महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बम्हरा ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 54 लाख लड़कियों को छात्रवृत्ति दी गई है जिसकी कुल रकम 510 करोड़ रु. होती है। वित्तीय साक्षरता की एक योजना भी शुरू की गई है जिससे पढ़ाई छोड़ चुकी महिलाओं द्वारा झेली जा रही समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

ASIAN DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE
BSIDC Colony, Off Boring-Patliputra Road, Patna - 800 013, Tel. : 0612-2575649, Fax : 0612-2577102
E-mail : adripatna@adriindia.org / adri_patna@hotmail.com, Website : www.adriindia.org

आइजीसी इंडिया विशेष व्याख्यान में सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज की निदेशक ज्योत्स्ना झा ने राय प्रकट की कि व्यापक लैंगिक समानता की दिशा में निश्चित तौर पर प्रगति हुई है। उनकी राय थी कि जिन क्षेत्रों में महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर ऊंची होती है उनमें लड़कों को कम तरजीह मिलती है। इसके बाद एक पैनल चर्चा हुई जिसका विषय था - महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण: बाधाएं और समाधान। इसकी अध्यक्षता महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बम्हरा और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के सचिव देवेश सेहरा ने सह-अध्यक्षता की। श्री सेहरा ने इस बात को लेकर कहा कि भारत में कोविड के दौर में 60 प्रतिशत पुरुषों की नौकरी बची रही जबकि मात्र 16 प्रतिशत महिलाएं अपनी नौकरी बचा सकीं क्योंकि कंपनियों को महिलाओं को काम पर रखने में अधिक खर्च करना पड़ता है। इस सत्र में आद्री की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अस्मिता गुप्ता ने कहा कि हम किस तरह का विकास चाहते हैं, इसकी जांच करने की जरूरत है। पहले भारत में नौकरी-विहीन विकास हो रहा था जिसके कारण ढेर सारी महिलाएं विनिर्माण कार्यों में काम पाने से वंचित हो गईं। पैनल चर्चा के अन्य सहभागियों में सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज की वरिष्ठ शोध सलाहकार निवेदिता मेनन, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रलय की पूर्व जेंडर बजट विशेषज्ञ पारामिता मजूमदार और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जेंडर विशेषज्ञ सुगंधा मुंशी शामिल थीं।

बाद में 'जेंडर और स्वास्थ्य: मुद्दे, साक्ष्य और नीतिगत प्रतिक्रिया' शीर्षक एक अन्य पैनल चर्चा भी हुई जिसकी अध्यक्षता डॉ. एन. विजय लक्ष्मी ने की। चर्चा का संचालन डॉ. अस्मिता गुप्ता ने किया और पैनल में बिहार यूनीसेफ की फील्ड ऑफिस की मुख्य अधिकारी नफीसा बिंत शफीक, सैन दियागो स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सेंटर ऑन जेंडर इक्विटी एंड हेल्थ की शोध-विज्ञानी नंदिता भान, सेहत की वरिष्ठ सलाहकार पद्मा देवस्थली, कोलकाता स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज की एसोसिएट प्रोफेसर शाश्वता घोष, और एकजुट इंडिया के कार्यक्रम विशेषज्ञ विकास नाथ ने भाग लिया। महिला, कृषि और सहकारिता पर आयोजित पैनल चर्चा में बिहार सरकार के सहकारिता विभाग की सचिव बंदना प्रेयशी ने अध्यक्ष के रूप में समापन वक्तव्य दिया। चर्चा का संचालन आद्री के सदस्य सचिव प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने किया। चर्चा की अन्य सहभागियों में कॉम्फेड की प्रबंध निदेशक शिखा श्रीवास्तव और सुगंधा मुशी शामिल थीं।

प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने कहा कि बिहार राज्य एक दिलचस्प स्थिति प्रस्तुत करता है कि राज्य में महिलाओं का शैक्षिक स्तर बढ़ रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के अनेक सरकारी कार्यक्रमों की मौजूदगी के बावजूद महिलाओं की कार्य-शक्ति सहभागिता दर (एलपीएफआर) में वृद्धि नहीं हुई है। हरजोत कौर बम्हरा ने समापन टिप्पणी की।

(Anjani Kumar Verma)

ASIAN DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE
BSIDC Colony, Off Boring-Patliputra Road, Patna - 800 013, Tel. : 0612-2575649, Fax : 0612-2577102
E-mail : adripatna@adriindia.org / adri_patna@hotmail.com, Website : www.adriindia.org